भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

28 अप्रैल 2011

जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलनरत जनता पर पुलिस की गोलीबारी और गिरफ्तारियों की निंदा करो! जैतापुर संयंत्र समेत देश में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द करने के लिए संघर्ष करो!

18 अप्रैल 2011 को जैतापुर के 9,900 मेगावाट वाले प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रही जनता पर पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता तबरेज़ सोयेकर (32) की मौत हुई जो नाटे गांव का निवासी था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला आदमी था। आठ अन्य प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गए। विरोध-प्रदर्शनकारियों ने एक अस्पताल पर हमला कर दिया ताकि वहां पर सरकारी शव-परीक्षण को रोका जा सके क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं था कि सरकार निष्पक्ष शव-परीक्षण करवाएगी। जापान में फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र में हुए परमाणु हादसा के बाद तेजी पकड़ने वाले इस चार साल पुराने आंदोलन ने अच्छा-खासा अनुभव प्राप्त किया था जिससे सरकार की संवेदनहीनता को समझा जा सके।

बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों की अनदेखी करते हुए तथा पीड़ितों को मुआवजा देने या आश्वस्त करने की कोई कोशिश नहीं करते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और महाराष्ट्र सरकार (जो साम्राज्यवादियों के पालतू कत्ते हैं) ने अपना मंतव्य दोहराया कि वे 'दुनिया के इस बहुत बड़े परमाणु बिजली सुमदाय' के निर्माण को जारी रखेंगे जिसमें छह रिएक्टर होंगे। दरअसल, सरकार ने फुकुशिमा त्रासदी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए 'किसी भी कीमत पर' परमाणु बिजली पार्क को बनाने की जो नीति अपनाई, उसके खिलाफ हुआ था उपरोक्त विरोध प्रदर्शन।

पुलिस ने करीब 100 लोगों और जाने-माने कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया, जो भारत के हर कोने (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्यप्रदेश) से इकट्ठे हुए थे ताकि 23 से 25 अप्रैल तक तारापुर से, जहां भारत का पहला परमाणु बिजली प्लांट की स्थापना हुई, जैतापुर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय परमाणु-विरोधी यात्रा में भाग लिया जा सके। दरअसल, फुकुशिमा के बाद परमाणु बिजली परियोजनाओं के खिलाफ देश में चारों तरफ, खासकर हरियाणा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश में कुछ नए और कुछ पहले से चले आ रहे विरोध-प्रदर्शनों का एक सिलसिला ही चल पड़ा। लेकिन इससे हमारे बहरे शासकों के कान में जूं तक नहीं रेंगी।

इस परमाणु संयंत्र के तहत पांच गांव - मडबन, निवेली, करेल, मितगावणे और सखारी नाटे आते हैं जो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के जैतापुर क्षेत्र में स्थित हैं और यह भूकम्प के प्रभाव में आ सकने वाला क्षेत्र है। यहां पर 968 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया। इस संयंत्र से 40 हजार जनता प्रभावित होगी जिसमें 16 हजार आबादी मछवारों की है।

फुकुशिमा हादसे के बाद जहां कई देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दोबारा विचार कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़िग है। इस सचाई को छिपाकर कि भारत के रिएक्टरों को दुनिया के सबसे अक्षम और खतरनाक माने जाते हैं, कुछ जन-विरोधी वैज्ञानिक जनता को गुमराह करने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं कि भारत के सुरक्षा मानक जापान से भी बेहतर हैं! जयराम रमेश जो अभी तक खुद को पर्यावरणवादी मंत्री कहते नहीं थकते थे, अब यह कहते हुए कि परमाणु ऊर्जा का कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने अपना असली कॉर्पोरेट-अनुकूल चेहरा दिखा दिया है। वह अब मनमोहनसिंह की भाषा बोल रहे हैं जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भारत-अमेरिका परमाणु करार पर दस्तखत कर परमाणु कम्पनियों से मिली अरबों रुपए की दलाली से वोट खरीदे थे। जब समूची दुनिया विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तलाश रही है, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, मानों हम सब भारतीय बेवकूफ हों जो इस बकवास पर विश्वास करें। अगर घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की बिजली की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी हैं तो यहां सब कुछ संभव है। लेकिन ऐसे देश में जहां मुकेश अम्बानी का एक महीने का बिजली बिल 71 लाख रूपए का है और जहां बिजली की भारी खपत की जरा भी परवाह किए बिना

दिन और रात के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि संकट में फंसे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं जिसका एक कारण बिजली की किल्लत भी है। लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में मद्धिम रोशनी देने वाली एक बत्ती तक नहीं है। ऐसे में यह कयास लगाया जा सकता है कि मंत्री महोदय किन लोगों की ऊर्जा की जरूरतों की बात कर रहे हैं। केन्द्र और राज्यों की दलाल सरकारों ने भारत के व्यापक ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद अपार खनिज भण्डारों का उत्खनन करने के लिए सैकड़ों एमओयू पर दस्तखत कर रखे हैं। खदानों और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत है। कार्पोरेट कम्पनियों की इन जरूरतों ने ही जयराम रमेश, मनमोहनसिंह जैसे लोगों को पागल बना दिया है जो जनता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद भी बिजली संयंत्रों को बनाने पर आमादा हैं। जनता की आजीविका, देश के पर्यावरण की सुरक्षा आदि मुद्दे जो विरोध-प्रदर्शनकारी उठा रहे हैं वो इनके लिए बेतुके हैं। एक मात्र समाधान जो वो जानते हैं वह है उन्हें 'कानून और व्यवस्था' की समस्या के रूप में देखना।

और तो और, हम यह कभी नहीं जान पाएंगे (बशर्तेकि कोई और विकी 'लीक' सामने न आ जाए) कि हमारे दलाल शासकों ने फ्रांस की कम्पनी 'आरेवा' से कितनी दलाली ले रखी होगी जिससे हम रिएक्टर आयात कर रहे हैं जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे परमाणु-अनुकूल देशों ने इस कम्पनी को डिजाइन क्लियरेन्स देने से इनकार कर दिया। दुनिया में अभी तक एक भी इवोल्यूशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर (ईएफआर) का न तो निर्माण हुआ और न ही उसकी सुरक्षा की जांच हो पाई जिससे ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय और असुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। फिर भी अपने साम्राज्यवादी आकाओं के तलवे चाटने वाले हमारे शासक उन्हें खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं जबकि वो मानवीय और पर्यावरणीय क्षति का जरा भी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं।

फुकुशिमा हादसे ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उसका संहारक परमाणु विकिरण का प्रभाव दसियों हजार सालों तक रहेगा। स्वतंत्र यूरोपियाई चिकित्सा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि रिएक्टर के 200 किलोमीटर के दायरे में 4 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से ग्रस्त होंगे और इस संयंत्र का विकिरणीय प्रदूषण पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 25 साल पहले चेर्नोबिल में हुए परमाणु हादसे के बाद चार लाख लोगों को खाली कराया गया था। अन्य दसियों लाख लोग अभी भी लगातार प्रदूषित वातावरण में डर के साये में जीने को मजबूर हैं कि कभी भी उन्हें कैंसर जकड़ ले सकता है और उनकी कई आने वाली पीढ़ियां गंभीर बीमारियों के साथ जन्म ले सकती हैं। अभी तक करीब दस लाख लोग उसके विलम्बकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों से मारे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। अगर जैतापुर में कोई बड़ा हादसा होगा तो समूचे रत्नगिरी जिले को पूरी तरह खाली करवाना पड़ेगा और पुणे व मुम्बई समेत समूचा पश्चिम महाराष्ट्र दसियों हजार सालों तक विकिरणीय प्रदूषण से ग्रस्त रहेगा।

जैतापुर की कोंकणी जनता जो इन सभी दुष्प्रभावों से, खासकर फुकुशिमा के बाद अच्छी तरह वाकिफ है, इस परमाणु संयंत्र के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रही है। सरकार ने इस संघर्ष को दबाने के लिए एक बर्बर दमन अभियान छेड़ दिया। लाठीचार्ज, धारा 144 और धारा 37(3) को लागू करना जिसके तहत लोगों की सभी किस्म की गोलबंदी पर प्रतिबंध रहेगा, मारपीट, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करना (जिसमें एक हत्या का प्रयास भी है!) और अब पुलिसिया गोलीबारी। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ रत्नगिरी जिला छोड़ने का आदेश जारी किया गया। नारायण राणे ऐसी धमकियां भी दे रहे हैं कि जो लोग जिले में कदम रखेंगे वो जिंदा लौटकर नहीं जाएंगे! पुलिस ने मीडिया को यह भी बताया कि वह इस आंदोलन पर कड़ी नजर रख रही है ताकि 'नक्सलवादियों के साथ संभावित सम्बन्धों' का पता लगाया जा सके, जोकि उसकी चिर-परिचित धमकी है। इस संघर्ष का समर्थन करने वाले इस क्षेत्र के जाने-माने नागरिकों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों से जैतापुर आंदोलन का हौसला कम नहीं हुआ जो पूरे भारत में विभिन्न ज्वलंत मसलों को लेकर लड़े जा रहे समझौताहीन संघर्षों में एक और मिसाल बनकर शामिल हो रहा है।

पिछले चार सालों के दौरान जब यह आंदोलन चल रहा था, चुप्पी साधकर रहने वाली शिवसेना ने अब इसमें प्रवेश किया क्योंकि वह इसमें कोंकण इलाके में नारायण राणे के दल बदलने के बाद खोई हुई जमीन को फिर से पाने की संभावना देख रही है। राजनीतिक रूप से सचेतनशील जैतापुर जनता को चाहिए कि वह इन अवसरवादियों को, जिन्होंने एनरॉन को अरब सागर में फेंक देने का दावा किया था और सत्ता में आने के बाद बात बदल दी थी, अपने स्वार्थ हितों के लिए इस संघर्ष को गुमराह करने का कोई मौका न दे। परमाणु करार के मुद्दे पर अपने आपको चैम्पियन के रूप में पेश करने वाली सीपीएम, परमाणु ऊर्जा को एक मात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले सरकारी के फैसले के खिलाफ मजबूत हो रहे इस मोर्चे पर कहीं नहीं दिख रही है। आंध्रप्रदेश में तेलुगुदेशम जैसी विपक्षी पार्टियां हालांकि बिजली संयंत्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, लेकिन जब एक बार वे सत्ता में आएंगी तो यही काम करेंगे क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड यही बता रहा है। जहां एक तरफ परमाणु बिजली संयंत्रों का विरोध करने वाली सभी तरह की ताकतों को एकजुट कर एक विशाल

आधार पर संघर्ष को व्यापक बनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ हितों या वोट बैंक की राजनीति के लिए संघर्ष को असल मुद्दे से भटका देने की सभी किस्म की साजिशों के प्रति जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

भाकपा (माओवादी) यह मांग करती है कि जैतापुर परमाणु पार्क समेत भारत में प्रस्तावित सभी परमाणु बिजली संयंत्रों को रद्द किया जाए। परमाणु प्लांट से उत्पन्न होने वाले खतरों से अपनी जिंदगियों और पर्यावरण को बचाने के लक्ष्य से लड़ रही कोंकणी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जा रहे दमनकारी कदमों का हमारी पार्टी खण्डन करती है। 18 अप्रैल को हुई गोलीबारी की न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग करते हैं। परमाणु-विरोधी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए सभी फर्जी मुकदमों, अवैध जिला-बदर आदेश और प्रतिबंधों को वापस लिया जाए। दरअसल रत्नगिरी के लोगों को यह घोषणा करनी चाहिए कि नारायण राणे जैसे लोगों को, जो संसाधनों से समृद्ध कोंकणी तटवर्ती इलाके को साम्राज्यवादियों को बेचने और उनकी आजीविका को तबाह करने पर आमादा हैं, इस इलाके में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है, न कि परमाणु-विरोधी कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए निस्वार्थपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं।

आइए, हम यह घोषणा करें कि हमें किस तरह का विकास या ऊर्जा के स्रोत चाहिए यह तय करने का अधिकार देश की जनता को ही होना चाहिए, न कि भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं को जो साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नमकहलाल नौकरों की तरह काम करते हैं। आइए, हम कोंकणी जनता के परमाणु संयंत्र विरोधी संघर्ष का दृढ़तापूर्वक समर्थन करें और शासक वर्गों द्वारा बढ़ाए जा रहे बिजली के असुरक्षित और खतरनाक विकल्प के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान का निर्माण करें। हमें तबरेज़ जैसों की कुरबानियों को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि रत्नगिरी की जनता ने घोषणा की।

आज हमारा देश इस बात का गवाह है कि चारों तरफ जल-जंगल-जमीन, सच्चा लोकतंत्र, विकास, आत्मनिर्भरता आदि को केन्द्र में रखते हुए जनता के जुझारू संघर्षों का एक बाढ़ सा आया हुआ है। जनता इन संघर्षों को (कुछ को तो कई सालों से) शांतिपूर्ण और जुझारू तरीके से तथा भीषण दमन के बावजूद भी पीछे न हटते हुए संचालित कर रही है। ये सभी संघर्ष परस्पर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। वक्त का तकाज़ा है कि इन सभी संघर्षों को एक दूसरे के भाईचारे में और आपसी समर्थन में मजबूती से खड़े होकर एक साझा मंच में लाना चाहिए ताकि साम्राज्यवादियों, भारत के बड़े कॉर्पोरेट दैत्यों तथा सामंती सरदारों के खिलाफ लड़ा जा सके जो इन जन-विरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं और संघर्षरत जनता का दमन कर रहे हैं। भारत के तमाम संघर्षरत जन समुदायों का एक विशाल, समवेत और जुझारू आंदोलन ही इस देश और जनता को दरिद्रता के अंधेरे गर्त से बचा सकता है जिसमें जनता के दुश्मन हमें धकेलने की साजिश रच रहे हैं।

Abhay

(अभय)
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)